www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 280 | जौनपुर सोमवार, 01 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

गुजरात में आज से 2027 जनगणना की शुरुआत

गुजरात, (एजेंसी)। गुजरात में आज सोमवार से पहले चरण की जनगणना का शुभारंभ हो रहा है। इससे पहले 3.74 लाख से अधिक लोगों ने स्व–गणना पूरी कर ली है, क्योंकि राज्य उस प्रक्रिया में भाग लेने की तैयारी कर रहा है जिसे अधिकारी "भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल जनगणना अभ्यास" कहते हैं। देश के इतिहास में यह 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना है, जो गुजरात और शेष भारत में दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इस प्रक्रिया के प्रारंभ की घोषणा करते हुए जनगणना निदेशक सुजल मायात्रा ने सभी नागरिकों से राष्ट्रव्यापी गणना कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया। जनगणना निदेशक सुजल मायात्रा ने कहा, "राज्य भर में 1 जून से 30 जून तक मकानों की सूची और आवास जनगणना आयोजित की जाएगी। इस चरण के दौरान, जनगणना करने वाले लोग आवास की स्थिति, परिवार के विवरण, पीने के पानी के स्रोत, शौचालय सुविधाओं और अन्य संपत्तियों को कवर करने वाले कुल 33 प्रश्न पूछेंगे।" पहले चरण को हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस (एचएलओ) के नाम से जाना जाता है, जिसमें जनगणना करने वाले लोग आवास की स्थिति, परिवार की संरचना, पीने के पानी की उप लब्धता, स्वच्छता सुविधाओं और अन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे।

तरुण चुघ ने दोहराया पीएम मोदी का संदेश, पंजाब की पहचान लस्सी है, नशा नहीं

अमृतसर, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम श्मन की बातश के 134वें एपिसोड के बाद विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पंजाब की फेमस लस्सी पी और कहा कि पंजाब की असली पहचान नशे से नहीं, बल्कि दूध, दही, घी और लस्सी जैसी पारंपरिक खाद्य संस्कृति से ही है।राजनीति समाचार अमृतसर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। उन्होंने कहा कि पंजाब की असली पहचान नशे से नहीं, बल्कि दूध, दही, घी और लस्सी जैसी पारंपरिक खाद्य संस्कृति से है। इसलिए भाजपा का अभियान युवाओं को नशे से दूर कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।तरुण चुघ ने कहा कि पंजाब के गांवों और शहरों में यह अभियान लगातार चल रहा है। इस मुहिम में प्रदेश के कई प्रसिद्ध खिलाड़ी, कलाकार और अन्य जानी–मानी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। वे युवाओं को समझा रहे हैं कि नशा जीवन को बर्बाद करता है, जबकि स्वस्थ खानपान और सकारात्मक सोच उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है।

खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती जरूरी : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम सुरक्षा के मोर्चे पर मजबूत होंगे तो दुनिया भी मैत्री करेगी। कमजोर के आगे कोई नहीं झुकता। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, इसलिए पूरी बात कहना सीखें। भारत की ऋषि परंपरा प्रेरणा देती है कि "अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च" यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन सामने वाला देश व समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अंततः हिंसा ही अपनानी पड़ेगी। देश के दुश्मन के साथ यही हमारा धर्म है और भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ यह करती है। मुख्यमंत्री शनिवार को

राजधानी में 19 करोड़ रुपये की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका (नौसेना शौर्य संग्रहालय के द्वितीय चरण) के लोकार्पण अवसर पर उपस्थित सैन्य अधिकारियों, कार्मिकों व जन–समूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ इस वाटिका का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नौसेना बैंड की अनुपम प्रस्तुति ने श्रोताओं का मन मोह लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सोच बड़ी होती है और व्यक्ति बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है तो सकारात्मक परिणाम आता है, जो युवाओं को नई प्रेरणा प्रदान करता है। इस वाटिका में आने वालों को भारतीय नौसेना के बारे में जानकारी मिलेगी। हमारे सैनिक किन सम–विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं, यह भी जानने का अवसर मिलेगा। यह जानकारी युवाओं के जीवन में चुनौतियों से जूझने की प्रेरणा होगी। नौसेना का लक्ष्य उसकी विराट सोच का प्रतीक है। सीएम ने आदर्श वाक्य "नभः स्पृशं दीप्तम्" का जिक्र किया और कहा कि आकाश की ऊंचाइयां छूने के लिए बड़ी सोच भी चाहिए। संकुचित सोच या भाव से बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की संकल्पना को रखा है।

पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को दिया सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का नया आधार : मनोहर लाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाने और देश में शहरी गरीबों की आजीविका को मजबूत करने वाली एक प्रमुख योजना के रूप में उभरी है। इस योजना के प्रभाव का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी के लोन प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें गरिमा, आत्मविश्वास और वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक मान्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ने के अवसर सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडरों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और योगदान को मान्यता देते हुए, शहरी गरीबों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को मजबूत करने की दृष्टि से 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की।" उन्होंने आगे कहा, "इस योजना का उद्देश्य केवल बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराना ही नहीं था, बल्कि स्ट्रीट वेंडरों को गरिमा, आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक मान्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना भी था।" मनोहर लाल ने बताया कि पिछले छह वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत भारत भर में 75.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभ मिला है। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि देशभर में लाभार्थियों को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

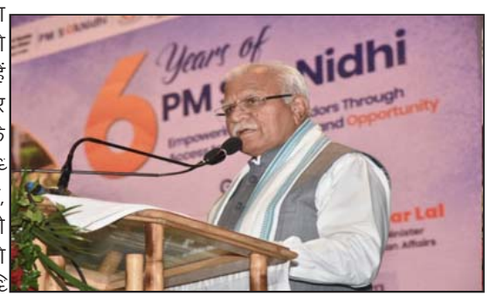

बंगाल में आज को मंत्रिमंडल का विस्तार, 35 मंत्री लेंगे शपथ

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन का दूसरा चरण सोमवार को पूरा होने जा रहा है। सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 35 नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा और 35 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 11 बजे नबन्ना (राज्य सचिवालय) में आयोजित होगा, जहां राज्यपाल आरएन रवि मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव दर्ज हुआ, क्योंकि पहली बार भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन का अंत किया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि ने सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। उनके साथ पांच अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक शामिल थे।

नीदरलैंड से लौटे चोलकालीन ताम्र–पत्र, भारत की विरासत को मिला गौरवपूर्ण सम्मान : नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में 11वीं सदी के 'चोल ताम्र–पत्रों' के बारे में बात की, जिन्हें उनकी हाल की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत वापस लाया गया था। इन 'चोल ताम्र–पत्रों' 21 बड़ी और 3 छोटी पट्टियां हैं, जो मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखी हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय के लिए यह एक खुशी का पल है। 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई बैठकों में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया, जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की

प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गईं। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश–विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनियाभर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है।" 'चोल ताम्र–पत्रों' के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और तीन छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला–प्रथम की ओर से अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी हैं। इनमें आनइमंगलम् गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।" उन्होंने कहा कि चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "'ज्ञान भारतम् अभियान' के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है।

देश की उपासना समाचार पत्र के संपादक व उनकी टीम ने किया ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संचालक बीके मुकेश भाई को सम्मानित

अयोध्या। सोमवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र साईं का पुरवा,दर्शन नगर के संचालक बीके मुकेश भाई द्वारा अयोध्या में सेवा केंद्र एवं शिव सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक और सनातन धर्म के विकास कार्यों के साथ साथ नशा मुक्त भारत और कोबेदार वृक्ष जिसे राम राज्य संकल्प वृक्ष भी कहते है उक्त की स्थापना के लिए किए जा रहे सराहनीय कार्यों हेतु उनको देश की उपासना दैनिक समाचार पत्र की संपादक किरन देवी श्रीवास्तव, प्रभु दयाल श्रीवास्तव, के साथ अयोध्या जिले के ब्यूरो चीफ राजेश श्रीवास्तव, जिला संवाददाता डॉ अजय कुमार तिवारी, सिटी रिपोर्टर राजन तिवारी, इसी समाचार पत्र के यूट्यूब चौनल ब्यूरो चीफ सुरेंद्र कुमार एवं उनकी धर्म पत्नि सहित सभी ने

बीके मुकेश भाई को श्री राम दरबार का स्मृति चित्र तथा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन बहुत भागदौड़ से भरा है, ये सिखाते हैं कि बिना अपनी जिम्मेदारियों को छोड़े गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान को कैसे याद करना है। जीवन जीने की असली कला क्या है कैसे आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपनी आंतरिक शांति और खुशी को खोने से रोक सकते हैं। हम सब शरीर नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा हैं, जो माथे के बीच भृगुटी के मध्य निवास करती है। इस सत्य को स्वीकार करने से अहंकार, ईर्ष्या और भेदभाव सब खत्म हो जाते है। उन्होंने बताया कि इस समय अयोध्या और आस–पास के क्षेत्रों में वे नशा मुक्त अभियान के तहत कोबेदार का वृक्ष जिसे रामराज्य संकल्प वृक्ष के नाम से जाना जा रहा है लगवाकर सच्चा गीता ज्ञान का उपदेश देते हैं कि नशा केवल शरीर को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुख–शांति को नष्ट कर देता है। सच्ची आत्मिक शक्ति से ही हर प्रकार के व्यसन से मुक्ति पाई जा सकती है।

राहुल गांधी के समर्थन पर अभिषेक बनर्जी ने दिया धन्यवाद

कोलकाता, (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद राहुल गांधी ने उनका हाल जाना था। इसे लेकर अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने लिखा कि राहुल जी, आपकी चिंता और लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद। भारतउन्होंने लिखा कि पिछले साल मैंने श्ऑपरेशन सिंदूरश के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पांच देशों की यात्रा की थी। मैंने अपने देश का बचाव किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा रहा। आज, मैं राजनीतिक हिंसा और राज्य प्रायोजित आतंकवाद का शिकार बनकर खड़ा हूं। यह आतंकवाद जिसे उन लोगों ने फैलाया है जो खुद को राष्ट्रवाद का रक्षक होने का दावा करते हैं। राजनीति समाचार उन्होंने लिखा कि यही आज की भाजपा की असलियत है। अगर आप उनका समर्थन करते हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप उन पर सवाल उठाते हैं, तो आप निशाना बन जाते हैं। अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं, तो आपका गुणगान होता है। अगर आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं, तो वे आपको चुप कराने की कोशिश करते हैं।अभिषेक ने लिखा कि मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करके आराम की जिंदगी जीने के बजाय लोकतंत्र की रक्षा करते हुए धमकियों का सामना करना ज्यादा पसंद करूंगा। सत्ता अस्थायी होती है।

गिरिजा अम्मा के संकल्प को पीएम मोदी का सलाम, सैनिकों के लिए जुटाए 40 लाख रुपये

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के नागरकोइल की एक शिक्षिका गिरिजा अम्मा से हुई अपनी मुलाकात का अनुभव शेयर किया। पीएम मोदी ने गिरिजा अम्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, "पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध 'मन की बात' से भी जुड़ा है। इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब तीन दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं, गिरिजा अम्मा की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा छात्र भी उनके साथ थे।" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गिरिजा अम्मा करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जयगोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने 'मन की बात' से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के छात्रों को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने बताया, "गिरिजा अम्मा ने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन एक रुपया योगदान दें। यानी एक साल में हर छात्र की ओर से 365 रुपए जमा हुए। इस छोटे–छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।" प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में इस स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत–बहुत बधाई देता हूं और उन छात्रों की भी विशेष सराहना करता हूं, जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष ढिल्लों हमेशा से कैप्टन अमरिंदर के करीबी माने जाते थे – सीएम मान

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों हमेशा से कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते थे और श्अब दोनों नेताओं के रास्ते अलग होते दिख रहे हैंश। मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि केवल सिंह ढिल्लों हमेशा से कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते थे। अब, दोनों नेताओं के रास्ते अलग होते दिख रहे हैं, और इस बदलाव के कारण केवल वे ही जानते हैं। दोनों के बीच गर्मजोशी में कमी क्यों आई है, यह एक रहस्य बना हुआ है।वे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस बयान पर मीडिया के सवाल का

जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ढिल्लों को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने से खुद को अलग करते हुए कहा था कि पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए गए इस फैसले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ढिल्लों का तब समर्थन किया था जब उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव संगरूर से लड़ा था। उन्होंने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी भाजपा से अधिक सीटें हासिल की हैं। पंजाब की जनता ने भाजपा को पांचवें स्थान पर धकेल दिया है। यह फैसला स्पष्ट रूप से जनता द्वारा भाजपा के नकारात्मक एजेंडे को खारिज करने को दर्शाता है।राज्य के भावी राजनीतिक परिदृश्य के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, अकाली और भाजपा दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान के लिए लड़ेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी जनता के आशीर्वाद और समर्थन से आराम से सरकार बनाएगी।राजनीति समाचार उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनावों में अपनी करारी हार से स्तब्ध विपक्षी दल उन चुनावों पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें उन्होंने राज्य में अब तक के सबसे शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव बताया।

संपादकीय

मानवीय प्रयास के बाद स्थिति चिंताजनक

जलवायु परिवर्तन से जुड़े नए परिदृश्य जब भी जारी किए जाते हैं, तो उनमें हमेशा एक गहरी दिलचस्पी होती है। ये परिदृश्य बताते हैं कि भविष्य में मौसम कैसा होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उत्सर्जन कम करने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाते हैं। हाल ही में, घोषित सात नए परिदृश्यों में एक उच्च उत्सर्जन वाला परिदृश्य 'आरसीपी 8.5' व उसका उत्तराधिकारी 'एसएसपी 5–8.5', अब हटा दिया गया है। इन परिदृश्यों में माना गया था कि वर्ष 2100 तक पृथ्वी का तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता था। वैज्ञानिकों ने इस परिदृश्य को इसलिए हटाया, क्योंकि दुनिया में जलवायु कार्रवाई का असर दिखने लगा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत वाहन व बैटरी तकनीक के विस्तार ने उत्सर्जन वृद्धि की रफ्तार को धीमा किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वैज्ञानिक भविष्यवाणियां गलत थीं, बल्कि मानव प्रयास कुछ हद तक सफल रहे हैं।

फिर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वैश्विक उत्सर्जन अब भी रिकॉर्ड स्तर पर है। लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के बाद ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। चरम गर्मी, बाढ़, सूखा व समुद्र स्तर में वृद्धि जैसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। भविष्य तय नहीं है। इसलिए, वैज्ञानिक कई संभावित जलवायु परिदृश्य तैयार करते हैं। ये परिदृश्य ऊर्जा उपयोग व वैश्विक नीतियों में संभावित बदलावों के आधार पर बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन अलग–अलग जलवायु मॉडलों के माध्यम से करते हैं, ताकि भविष्य के प्रभावों का ज्यादा सटीक अनुमान लगाया जा सके। पहले यह उम्मीद थी कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सकता है, लेकिन अब सबसे बेहतर संभावना में भी तापमान लगभग 1.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वर्तमान नीतियों के आधार पर दुनिया लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की दिशा में बढ़ रही है। 'आरसीपी 8.5' को हटाना प्रगति का संकेत है कि हमने सबसे खराब संभावित स्थिति से बचाव कर लिया है। लेकिन सबसे अच्छे भविष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। अगले पांच वर्ष बेहतर या बदतर जलवायु भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे कदमों को और तेज करना होगा, जो सबसे बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

आर्थिक वृद्धि और निजी निवेश को बढ़ावा देने की पहल

रंजीत

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका के सबसे कमजोर इलाकों को एक नए डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत है ऐसा मॉडल जो मदद पर कम और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा निर्भर हो। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब मानवीय जरूरतें बढ़ रही हैं, जबकि इंटरनेशनल मदद बजट पर दबाव है। रिपोर्ट के मुताबिक, अफ्रीका में कई समुदाय गरीबी, संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता के चक्र में फंसे हुए हैं क्योंकि डेवलपमेंट की कोशिशें अक्सर लंबे समय की आर्थिक ग्रोथ के बजाय शॉर्ट–टर्म राहत पर फोकस करती हैं। लेखकों का कहना है कि नौकरियां बनाना, बिजनेस को सपोर्ट करना और प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना लंबे समय तक चलने वाला लचीलापन बनाने के लिए जरूरी होगा।

रिस्क को मौके में बदलना कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल अनिश्चितता और फाइनेंस तक सीमित पहुंच के कारण फ्रंटियर मार्केट को अक्सर हाई–रिस्क डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि यही इलाके बड़े मौके भी देते हैं। कई इलाकों में आबादी बढ़ रही है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है और एंटरप्रेन्योरशिप की संभावना का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद, अफ्रीका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अट्रैक्ट कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट आता भी है, उसका ज्यादातर हिस्सा नेचुरल रिसोर्स में ही होता है, जिससे कई लोकल बिजनेस को बढ़ने के लिए जरूरी कैपिटल नहीं मिल पाता। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन्वेस्टर और सरकारों को नाजुक इलाकों को न सिर्फ डेवलपमेंट की चुनौतियों के तौर पर देखना शुरू करना चाहिए, बल्कि उभरते हुए इकोनॉमिक मौकों के तौर पर भी देखना चाहिए।

सरकारों और पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक नई भूमिका रिपोर्ट का एक सबसे मजबूत मैसेज पॉलिसी बनाने वालों के लिए है। सरकारों को पारंपरिक डेवलपमेंट के तरीकों से आगे बढ़ने और ऐसे हालात बनाने पर ध्यान देने के लिए बढ़ावा दिया जाता है जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। इसमें रेगुलेशन में सुधार, इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना, बिजनेस में रुकावटों को कम करना और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना शामिल है। रिपोर्ट के पॉलिसी से जुड़े जरूरी मतलब हैं। जैसे–जैसे कई अफ्रीकी देश बढ़ते कर्ज और घटते पब्लिक बजट का सामना कर रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना डेवलपमेंट को फाइनेंस करने का एक अहम टूल बन सकता है। सिर्फ सरकारी खर्च या डोनर फंडिंग पर निर्भर रहने के बजाय, पॉलिसी बनाने वाले प्राइवेट कैपिटल के बड़े फ्लो को अनलॉक करने के लिए सुधारों और पार्टनरशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

रिपोर्ट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मानवीय मामलों के लिए जिम्मेदार मिनिस्ट्री के बीच ज्यादा करीबी सहयोग को भी बढ़ावा देती है। इस तरह का कोऑर्डिनेशन यह पक्का करने में मदद कर सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोटेक्शन के मकसद एक–दूसरे को मजबूत करें। सिर्फ मदद देना नहीं, बल्कि मार्केट बनाना रोडमैप में सरकारों, इन्वेस्टर्स, डेवलपमेंट एजेंसियों, मानवीय संगठनों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के बीच मजबूत सहयोग की बात कही गई है। अलग–अलग काम करने के बजाय, ये लोग इन्वेस्टमेंट के मौकों की पहचान करने और रिस्क कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

एक खास तौर पर जरूरी सुझाव यह है कि मानवीय और डेवलपमेंट संगठन लोकल बिजनेस को उनके खरीदने के फैसलों में सपोर्ट करें। लोकल लेवल पर ज्यादा सामान और सर्विस खरीदकर, मदद एजेंसियां घ्लोकल कंपनियों के लिए डिमांड बना सकती हैं, जिससे उन्हें बढ़ने और इन्वेस्टमेंट लाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवीय खर्च सिर्फ इमरजेंसी का जवाब देने के बजाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक कैटलिस्ट बन सकता है। रोडमैप गारंटी, कंसेशनल फाइनेंस और ब्लेंडेड फाइनेंस स्ट्रक्चर जैसे फाइनेंशियल टूल्स को भी बढ़ावा देता है जो इन्वेस्टर्स को उन मार्केट में आने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं जिनसे वे वरना बचते हैं। रोडमैप क्यों जरूरी है इस प्रपोजल के सेंटर में देशों के अलायंस बनाना है जो सरकारों, इन्वेस्टर्स और लोकल ऑर्गनाइजेशन को एक साथ लाकर इन्वेस्टमेंट में रुकावटों की पहचान करने और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाने में मदद करेंगे।

कर्नाटक में बदलाव के बाद की चुनौतियां

संजय

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के त्यागपत्र देने के साथ ही उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के राज्य की कमान संभालने का रास्ता साफ हो गया। इससे शिवकुमार की तो चाहत पूरी हो गई, लेकिन यह कहना कठिन है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ सामान्य होने जा रहा है या फिर राज्य की विभिन्न समस्याओं के समाधान की राह आसान हो गई है। सिद्दरमैया ने त्यागपत्र देने की घोषणा करते हुए यह कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने जैसा कहा, मैंने वैसा किया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा आकर कांग्रेस की केंद्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय होने का आग्रह ठुकराते हुए कहा कि वे राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे। चूंकि सिद्दरमैया जमीनी स्तर की राजनीति करने वाले नेता हैं और उनका अपना जनाधार है, इसलिए वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे शिवकुमार के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसके नतीजे में वहां नए सिरे से गुटबाजी भी पनप सकती है, क्योंकि शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल से सिद्दरमैया के कुछ समर्थक बाहर हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्वाभाविक ही है कि शिवकुमार अपने हिसाब से शासन से चलाएंगे और इसके लिए वे प्रशासन में भी पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों को किनारे कर सकते हैं। इसके आसार कम ही हैं कि सिद्दरमैया अपने उत्तराधिकारी शिवकुमार के लिए खुला मैदान छोड़ेंगे, क्योंकि जमीनी राजनीति करने वाला कोई नेता अपना राजनीतिक वर्चस्व इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अपने देश में तो ऐसा और भी कम होता है। अपने यहां उम्रदराज नेता तब तक राजनीति से रिटायर ही नहीं होते, जब तक उन्हें बिल्कुल किनारे न कर दिया जाए। कांग्रेस सिद्दरमैया की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। शिवकुमार 2023 में तभी से मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी थे, जब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने वरिष्ठता के आधार पर सिद्दरमैया का चयन किया। शिवकुमार का दावा था कि उनके और सिद्दरमैया के बीच इसे लेकर सहमति कायम हुई थी कि दोनों ढाई–ढाई वर्ष तक सत्ता संभालेंगे। अपने इस दावे के अनुरूप वे पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री पद हासिल करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सिद्दरमैया पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान के दबाव में वे तीन वर्ष बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार

हुए। स्पष्ट है कि उन्होंने मजबूरी में पद छोड़ा। कर्नाटक की तरह एक समय राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी इसे लेकर खींचतना हुई थी कि दोनों के बाच ढाई–ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनने की सहमति बनी थी। सचिन पायलट ने बहुत कोशिश की कि इस कथित सहमति के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, लेकिन अशोक गहलोत टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों को भी ठुकरा दिया। इस कारण सचिन पायलट एवं उनके बीच खींचतान जारी रही और कांग्रेस आलाकमान अंत समय तक कोई फैसला नहीं कर सका। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ।

यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव के बीच इसे लेकर झगड़ा होता रहा कि ढाई–ढाई साल तक सत्ता संभालने की बात हुई थी। यहां भी कांग्रेस नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर सका। नतीजा यह हुआ कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की पराजय का एक कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान भी बनी।

कांग्रेस नेतृत्व ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को विधानसभा चुनाव के करीब एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए बाध्य किया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को मिली। इसके चलते गुटबाजी को बढ़ावा मिला और विधानसभा चुनावों में इसका लाभ आम आदमी पार्टी ने उठाया।

कर्नाटक में दो वर्ष बाद चुनाव होने हैं। कहना कठिन है कि तब क्या होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि कर्नाटक में 1980 के बाद कोई भी सरकार सत्ता में नहीं लौटी है। शिवकुमार इस सिलसिले को तोड़ सकेंगे, यह कहना इसलिए कठिन है, क्योंकि कर्नाटक कई समस्याओं से घिरा है।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु आइटी सिटी के रूप में विख्यात है, लेकिन इस समय बेंगलुरु के साथ देश भर का आइटी उद्योग समस्याओं से घिरा है। कर्नाटक में बेंगलुरु को छोड़कर एक दो शहर ही सही तरह विकसित हो पाए हैं। बेंगलुरु और शेष राज्य में जो आर्थिक असमानता दिखती है, वह यही बताती है कि सरकारों ने अन्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक उसी तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे अन्य कई राज्य। किसी भी दल के लिए कर्नाटक के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना इसलिए कठिन होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को संतुष्टि के नाम पर विकास के काम कम, लोकलुभावन योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह किसी से छिपा नहीं कि रेवड़ी राजनीति कर्नाटक के लिए एक समस्या बन गई है। लोकलुभावन योजनाएं पूरी करने के फेर में राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। ऐसी योजनाओं से एक तो मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपती है और दूसरे राज्य की वित्तीय सेहत बिगड़ती है।

ऐसा कुछ अन्य राज्यों में भी हो रहा है। कर्नाटक की तरह कई राज्यों में आर्थिक विकास राजधानी और चुनिंदा शहरों में ही केंद्रित दिखता है। अधिकांश राज्यों के पिछड़ेपन का कारण यही है कि वहां की सरकारें प्रदेश के समग्र विकास पर ध्यान नहीं देतीं। इससे आर्थिक असंतुलन और असमानता बढ़ती है। यह कर्नाटक में भी देखने को मिल रहा है। यह स्थिति शिवकुमार के लिए चुनौती बन सकती है।

प्रमुख राज्यों में देखा जाए तो कांग्रेस के पास तेलंगाना को छोड़कर कर्नाटक ही बचा है। यदि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से राज्य की सत्ता निकल गई और भाजपा सत्ता में आ गई तो उसका देशव्यापी प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस के लिए उसका मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। स्पष्ट है कि शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना तो तय हो गया, लेकिन उनके लिए राज्य को समस्याओं से उबार पाना आसान नहीं होने वाला।

ब्याज दरों में बढ़ोतरी से रोजगार पर पड़ता है सीधा दबाव

आदित्य

यूरोपियन सेंट्रल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम और बैंक डे फ्रांस के रिसर्चर्स की एक नई स्टडी हाल के सालों की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पहेलियों में से एक पर रोशनी डालती हैरू धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ और बार–बार लगने वाले झटकों के बावजूद यूरोप में रोजगार क्यों मजबूत बना रहा। महामारी के बाद, कई इकोनॉमिस्ट को उम्मीद थी कि बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि बिजनेस को कमजोर डिमांड, ज्यादा महंगाई और बढ़ती लागत का सामना करना पड़ा। इसके बजाय, कंपनियों ने ज्यादातर अपने वर्कर्स को बनाए रखा। स्टडी में कहा गया है कि यह ष्लेबर होर्डिंगष् के कारण था दृ यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कंपनियाँ बिजनेस एक्टिविटी धीमी होने पर भी कर्मचारियों को रखती हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि हालात सुधरेंगे या उन्हें डर होता है कि भविष्य में उन्हें फिर से वर्कर्स को काम पर रखने में मुश्किल हो सकती है।

मॉनेटरी पॉलिसी हायरिंग के फैसलों को कैसे प्रभावित करती है रिसर्चर्स ने 1999 और 2020 के बीच जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की दस लाख से ज्यादा फर्मों के डेटा का एनालिसिस किया, साथ ही 2023 तक बेल्जियम के डिटेल्ड क्वार्टरली डेटा का भी। उनके नतीजों से पता चलता है कि मुश्किल समय में कंपनियाँ वर्कर्स को बनाए रखेंगी या नहीं, यह तय करने में मॉनेटरी पॉलिसी एक अहम भूमिका निभाती है। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और फाइनेंसिंग की स्थिति अच्छी होती है, तो बिक्री या आउटपुट गिरने के बावजूद बिजनेस के कर्मचारियों को रखने की संभावना ज्यादा होती है। उधार लेने की कम लागत से फर्मों के लिए कुछ समय के नुकसान को सहना और सैलरी देना जारी रखना आसान हो जाता है।

हालांकि, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो कंपनियों पर ज्यादा फाइनेंशियल दबाव पड़ता है। जैसे–जैसे उधार लेना महंगा होता जाता है, फर्म ज्यादा स्टाफ को रखने के लिए कम तैयार या कम काबिल होती हैं, जिससे नौकरियों में ज्यादा कटौती होती है। रेट में बढ़ोतरी का रेट में कटौती से ज्यादा असर होता है स्टडी के सबसे जरूरी नतीजों में से एक यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी रोजगार पर बैलेंस्ड तरीके से असर नहीं डालती है। रिसर्च करने वालों ने पाया कि रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का लेबर मार्केट पर अकोमोडेटिव पॉलिसी की तुलना में ज्यादा असर होता है। आसान शब्दों में, इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी फर्मों को नौकरियां कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट में कटौती की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ावा देती है।

सालाना और तिमाही दोनों डेटा का इस्तेमाल करते हुए, स्टडी में पाया गया कि मॉनेटरी सख्ती का लेबर जमाखोरी पर असर मॉनेटरी ईजिंग के असर से लगभग दो से तीन गुना ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि सेंट्रल बैंक द्वारा रेट में बढ़ोतरी का रोजगार पर बड़ा असर हो सकता है, खासकर आर्थिक कमजोरी के समय में। छोटी फर्मों पर सबसे ज्यादा दबाव होता है स्टडी से यह भी पता चलता है कि सभी बिजनेस एक जैसा रिएक्ट नहीं करते हैं।

बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी फर्म मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। क्योंकि वे अक्सर बैंक लोन और बाहरी फाइनेंसिंग पर ज्यादा निर्भर रहती हैं, इसलिए बढ़ती ब्याज दरें उनके ऑपरेशन पर ज्यादा सीधा असर डालती हैं। रिसर्चर्स ने वर्कफोर्स स्किल्स के आधार पर भी अंतर पाया। जिन फर्मों में कम–स्किल्ड वर्कर्स का बड़ा हिस्सा होता है, वे बदलती फाइनेंशियल कंडीशंस पर ज्यादा मजबूती से रिएक्ट करती हैं। ज्यादा पढ़े–लिखे वर्कर्स वाली कंपनियाँ आमतौर पर स्टाफ को बनाए रखने के लिए ज्यादा तैयार रहती हैं क्योंकि स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉइज को बदलना महंगा और मुश्किल होता है।

फाइनेंशियल मजबूती मायने रखती है किसी फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ यह तय करने में अहम भूमिका निभाती है कि मंदी के दौरान वह वर्कर्स को बनाए रख सकती है या नहीं। जिन बिजनेस पर ज्यादा कर्ज होता है, वे हालात बिगड़ने पर नौकरी कम करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। इसके उलट, ज्यादा मुनाफा और अच्छी बैलेंस शीट वाली फर्में कुछ समय के झटकों को बेहतर तरीके से झेल पाती हैं और अपने वर्कफोर्स को बनाए रख पाती हैं। नतीजों से पता चलता है कि मॉनेटरी पॉलिसी न सिर्फ इकोनॉमिक डिमांड पर असर डालकर बल्कि फर्मों की फाइनेंस तक पहुंच को भी आकार देकर लेबर मार्केट पर असर डालती है। आसान फाइनेंशियल हालात कंपनियों को मुश्किल समय में वर्कर्स को बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि मुश्किल हालात नौकरियां कम करने का दबाव बढ़ाते हैं। जैसे–जैसे यूरोप अनिश्चित इकोनॉमिक माहौल में आगे बढ़ रहा है, स्टडी पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक जरूरी सबक बताती हैरू इंटरेस्ट रेट के फैसले सिर्फ महंगाई और उधार लेने की लागत पर ही असर नहीं डालते। वे इस बात पर भी असर डालते हैं कि जब इकोनॉमी धीमी होती है तो बिजनेस कितने वर्कर्स को अपने पेरोल पर रखने को तैयार और काबिल हैं।

साइबर सिक्योरिटी की तैयारी

विजय

साइबर सिक्योरिटी को अक्सर एक टेक्निकल जरूरत या हैकर्स से बचाव का एक तरीका माना जाता है। लेकिन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू के रिसर्चर्स की एक नई स्टडी से पता चलता है कि यह इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पावरफुल ड्राइवर भी हो सकता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिन देशों में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम ज्यादा मजबूत होते हैं, वे उन सेक्टर्स में तेजी से ग्रोथ करते हैं जो साइबर रिस्क के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, जिससे साइबर सिक्योरिटी डिजिटल डेवलपमेंट का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है।

जैसे–जैसे सरकारें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई–कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज में भारी इन्वेस्ट करती हैं, स्टडी का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी को अब दूसरी चिंता नहीं मानना घ्चाहिए। इसके बजाय, इसे एक अहम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखा जाना चाहिए जो देशों को डिजिटलाइजेशन के पूरे फायदे उठाने में मदद करता है। साइबर रिस्क पहले से कहीं ज्यादा क्यों जरूरी हैं

आजकल की इकॉनमी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। बिजनेस सप्लाई चेन को मैनेज करने, पेमेंट प्रोसेस करने, कस्टमर्स से बातचीत करने और जरूरी जानकारी स्टोर करने के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी पर इस बढ़ती निर्भरता ने एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में सुधार किया है, लेकिन इससे साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ गया है। रैनसमवेयर की घटनाएं, डेटा ब्रीच और डिजिटल नेटवर्क में रुकावट से ऑपरेशन रुक सकते हैं, लागत बढ़ सकती है और डिजिटल सिस्टम में भरोसा कम हो सकता है। सरकारों, अस्पतालों और बड़ी कंपनियों पर हाल के हमलों से पता चला है कि साइबर घटनाएं कैसे आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती हैं जो सीधे टारगेट किए गए संगठनों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं।

रिसर्च करने वालों का तर्क है कि साइबर रिस्क बराबर नहीं बंटे होते हैं। कुछ सेक्टर दूसरों की तुलना में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जिससे वे रुकावटों के प्रति ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इससे यह जांचने का मौका मिलता है कि क्या मजबूत साइबर सिक्योरिटी तैयारी वाले देश आर्थिक गतिविधियों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं और ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। वे सेक्टर जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है।

स्टडी में 178 देशों के पांच बड़े सेक्टरोंरू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और हॉस्पिटैलिटी, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन्स के डेटा का एनालिसिस किया गया। इसमें पाया गया कि जिन सेक्टर में साइबर रिस्क का ज्यादा खतरा था, उन्होंने उन देशों में लगातार बेहतर परफॉर्म किया जहां साइबर सिक्योरिटी की क्षमताएँ मजबूत थीं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन्स सबसे ज्यादा साइबर–एक्सपोज्ड सेक्टर के रूप में सामने आए, इसके बाद ट्रेड और हॉस्पिटैलिटी का स्थान रहा। ये इंडस्ट्री लगातार डिजिटल कनेक्टिविटी, रियल–टाइम डेटा फ्लो और सुरक्षित नेटवर्क पर निर्भर

करती हैं। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन कम एक्सपोज्ड पाए गए क्योंकि वे डिजिटल सिस्टम पर कम निर्भर करते हैं। नतीजों से पता चलता है कि साइबर सिक्योरिटी की तैयारी में बड़ा सुधार, कमजोर सेक्टर में सालाना लगभग एक से दो परसेंट ज्यादा ग्रोथ से जुड़ा है। यह देखते हुए कि सैंपल में औसत सेक्टर ग्रोथ हर साल लगभग दो परसेंट थी, इसका असर काफी है। आसान शब्दों में कहें तो, जो देश साइबर खतरों को रोकने और उनका जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं, वे उन सेक्टर में ज्यादा मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाते हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं। पॉलिसी बनाने वालों के लिए एक चेतावनी यह स्टडी उन सरकारों के लिए एक जरूरी मैसेज देती है जो डिजिटल बदलाव की स्ट्रेटेजी अपना रही हैं। पॉलिसी बनाने वाले अक्सर इंटरनेट एक्सेस बढ़ाने, डिजिटल सर्विस को बढ़ावा देने और टेक्नोलॉजी अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान देते हैं। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि अगर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर हैं तो इनके इकोनॉमिक फायदे कम हो सकते हैं। कोई देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है और बिजनेस को ऑनलाइन जाने के लिए बढ़ावा दे सकता है, लेकिन साइबर हमले ऑपरेशन में रुकावट डालकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा कम करके उन फायदों को तेजी से खत्म कर सकते हैं। इसलिए, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन के लिए एक जरूरी कॉम्प्लिमेंट के तौर पर काम करती है। यह पॉलिसी बनाने वालों के लिए, इसका मतलब है कि साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट को बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान में शामिल किया जाना चाहिए। साइबर कानूनों को मजबूत करना, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाना, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को बेहतर बनाना, डिजिटल स्किल्स में इन्वेस्ट करना, और इंस्टीट्यूशन्स के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, ये सभी मजबूत इकोनॉमिक नतीजों में मदद कर सकते हैं। ये नतीजे खास तौर पर डेवलपिंग देशों के लिए जरूरी हैं, जहाँ डिजिटल अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साइबर सिक्योरिटी कैपेसिटी बनाने से यह पक्का करने में मदद मिल सकती है कि नई टेक्नोलॉजी नई कमजोरियाँ पैदा करने के बजाय लंबे समय तक चलने वाले इकोनॉमिक फायदे दें। सिक्योरिटी खर्च से ग्रोथ इन्वेस्टमेंट तक स्टडी के सबसे जरूरी नतीजों में से एक यह है कि साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ एक खर्च के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। पारंपरिक रूप से, साइबर सिक्योरिटी पर खर्च को जोखिम कम करने के लिए डिजाइन किए गए एक बचाव के तरीके के तौर पर देखा गया है। नए सबूत बताते हैं कि यह प्रोडक्टिविटी को बचाकर, रुकावटों को कम करके और बिजनेस के भरोसे को बढ़ाकर आर्थिक फायदा भी कमा सकता है। स्टडी में पाया गया कि ज्यादा आय वाले देशों को साइबर सिक्योरिटी की तैयारी से और भी ज्यादा ग्रोथ फायदे मिलते हैं, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएँ ज्यादा डिजिटली इंटीग्रेटेड हैं। हालाँकि, डेवलपिंग अर्थव्यवस्थाओं को भी फायदा होता है, जो दिखाता है कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने से डेवलपमेंट के सभी लेवल पर ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। जैसे–जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनती जा रही हैं, साइबर सिक्योरिटी लचीलेपन, कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक नींव के तौर पर उभर रही है। सरकारों, बिजनेस और डेवलपमेंट संस्थानों के लिए, संदेश साफ हैरू साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना अब सिर्फ सिस्टम को बचाने के बारे में नहीं है। यह तेजी से आर्थिक मौकों को बचाने और बढ़ाने के बारे में है।

रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में मछलीशहर तहसील अंतर्गत क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी और गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित मांग पत्र एसडीएम को सौंपा और गैस वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव इरशाद खान ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकर गैस एजेंसी पर दलालों और बिचौलियों का कब्जा हो गया है, जिसके चलते आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि कई परिवार गैस की उपलब्धता न होने से परेशान हैं और लोगों को घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इरशाद खान ने कहा कि एक ओर जनता महंगाई की मार झेल रही है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। धरना–प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मछलीशहर के अध्यक्ष मुहम्मद सैफ ने कहा कि गैस एजेंसी पर प्रतिदिन लंबी कतारें लग रही हैं। लोगों को अपना रोजगार और जरूरी काम छोड़कर गैस लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कई बार सिलेंडर न मिलने पर उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष आरिफ सलमानी ने आरोप लगाया कि एजेंसी के कर्मचारी उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं और दलालों के माध्यम से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है। प्रदर्शन में जिला महासचिव एवं मछलीशहर प्रभारी अरुण शुक्ला, मल्हनी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉ. राकेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रेखा सिंह, जिला सचिव जब्बार अली सलमानी, रईस खान, मेराज अली, किरन, शीला, संतोषी सिंह, संजय कुमार सोनी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो पार्टी व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

'मधु राष्ट्रीय सलाहकार, लवी जिला उपाध्यक्ष और विकास जिला सचिव नियुक्त, एंटी करप्शन फोरम काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी हुई जारी'

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एंटी करप्शन फोरम काउंसिल ऑफ इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन की मासिक बैठक एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुयश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए मधु जी को राष्ट्रीय सलाहकार, लवी जी को जिला उपाध्यक्ष तथा विकास जी को जिला सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन के उद्देश्यों एवं दायित्वों के प्रति निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई गई।कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित कर उनके सामाजिक दायित्वों एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की सराहना की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुयश श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन समाज में पारदर्शिता, जागरूकता और जनहित के मुद्दों को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है तथा भविष्य में भी जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का संकल्प लिया।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू मुक्त भारत अभियान हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सद्भावना क्लब, जौनपुर द्वारा "तंबाकू मुक्त भारत अभियान" के अंतर्गत हस्ताक्षर कार्यक्रम का आयोजन सद्भावना पुल, जौनपुर पर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष डॉ. विवेकानंद मौर्य ने की। उपस्थित लोगों ने तंबाकू का सेवन न करने तथा अपने परिवार एवं समाज को इसके दुष्प्रभावों से बचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि तंबाकू अनेक गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है और इसके प्रति जन–जागरूकता समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में सद्भावना क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद रजा खान, पूर्व अध्यक्ष लालजी यादव, श्रावण साहू मधुसूदन बैंकर्स, हफीज शाह सहित , शाहबाज खान,धीरज गुप्ता , लोकेश जावा सैयद फरोग अहमद , चंद्रेश मौर्या, अभिनंदन त्रिपाठी, सूरज मौर्या,अतीत मौर्या, प्रखर गुप्ता सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक रविकांत जायसवाल ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। क्लब के अध्यक्ष डॉ. विवेकानंद मौर्य, सचिव हर्ष माहेश्वरी एवं कोषाध्यक्ष विनीत गुप्ता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में संकल्प लिया"तंबाकू छोड़ें, जीवन से नाता जोड़ें।" कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ तथा उपस्थित नागरिकों ने तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण हेतु सक्रिय योगदान देने का संकल्प व्यक्त किया।

चार वर्ष 10 माह बाद जौनपुर से विदा हुए बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल- यहां मिला प्यार जीवनभर नहीं भूलूंगा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर से जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल का तबादला सीतापुर जनपद के लिए कर दिया गया है। जुलाई 2021 में जौनपुर का कार्यभार संभालने वाले डॉ. पटेल ने करीब चार वर्ष 10 माह तक जिले में अपनी सेवाएं दीं। उनके कार्यकाल को बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, नवाचार और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के लिए याद किया जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान डॉ. पटेल ने विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा शासन की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष ध्यान दिया। मिशन प्रेरणा समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रही। डॉ. पटेल ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य संस्कृति को मजबूत किया। उनके प्रयासों का ही परिणाम रहा कि जिले के कई परिषदीय विद्यालयों ने प्रदेश स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ–साथ शिक्षकों

में विश्वास, संवाद और सहयोग का माहौल तैयार किया, जिससे शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिली। रविवार को अपने विदाई समारोह के दौरान बातचीत करते हुए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने जौनपुर से जुड़ी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, ष्मैं जुलाई 2021 में जौनपुर का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनकर आया था। इस जनपद की धरती ने मुझे जो प्यार, सम्मान और सहयोग दिया, वह मुझे आज तक कहीं नहीं मिला।ष उन्होंने कहा कि यहां के शिक्षकों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों का स्नेह उनके लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने जौनपुर में बिताए गए चार वर्ष 10 माह को अपने प्रशासनिक जीवन के सबसे संतोषजनक और यादगार वर्षों में से एक बताया। डॉ. पटेल के तबादले के साथ जिले में उनके कार्यकाल का एक सफल अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और कार्यों की छाप लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनी रहेगी।उनके विदाई के दौरान भव्य आयोजन किया गया।इस दौरान जिले के खंड शिक्षा अधिकारी,शिक्षक प्रधानाचार्य ,विभिन्न शिक्षक संगठन के लोगो ऑफिस पहुंचकर उनको पुष्प अर्पित करते हुए विदाई दिया।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती पर दो स्मृति द्वारों का लोकार्पण, विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने किया उद्घाटन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। यूपी के जौनपुर में लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को बदलापुर क्षेत्र के मरगूपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग–731 के किनारे विधायक निधि से निर्मित ष्लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर स्मृति द्वारष एवं ष्लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल स्मृति द्वारष का भव्य लोकार्पण विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय नागरिकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर भारतीय इतिहास की महानतम शासकों में से एक थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में जनकल्याण, न्याय, धर्म और संस्कृति के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका जीवन सेवा, त्याग और सुशासन का अनुपम उदाहरण है, जो आज भी समाज और नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होल्कर केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं थीं, बल्कि नारी शक्ति, करुणा और धर्मपरायणता की सशक्त प्रतीक भी थीं। उन्होंने देशभर में मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और तीर्थस्थलों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण का ऐतिहासिक कार्य कराया। काशी विश्वनाथ धाम, सोमनाथ मंदिर सहित अनेक धार्मिक स्थलों के विकास में उनका योगदान आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। वक्ताओं ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा और लोकहित के कार्यों के लिए समर्पित रहा। उनके आदर्श वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं और समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। स्मृति द्वारों का निर्माण उनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व को जन–जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, अपना दल (एस) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंचायत मंच गोकरण पटेल, डॉ. विकास पाल, उमाशंकर पाल, पवन पाल, राजनारायण पटेल, उदयभान पटेल, जिला महामंत्री पीयूष गुप्ता, अजय सिंह, राजकेशर पाल, आमोद सिंह, अंशु मौर्य, राखी सिंह, पुष्पा निषाद, रागिनी सिंह, प्रदीप पटेल, सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया।

कॉइन में निवेश के नाम पर 44 हजार की ठगी

लखनऊ संवाददाता। गोमतीनगर के ग्वारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने कॉइन में निवेश के नाम पर 44 हजार की ठगी का आरोप लगाया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। जितेंद्र के अनुसार, उन्हें व्हाट्सएप पर मेसेज कर जालसाज ने उन्हें केयू कॉइन में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा दिया। उन्होंने केयू कॉइन एप पर आईडी बनाकर 44 हजार रुपये जमा कर दिए। आरोप है कि ठग ने उनकी आईडी का एक्सेस लेकर पूरी रकम अपने खाते में हस्तांतरित कर ली। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि मामले की जांच साइबर सेल कर रही है।

नशा करने से मना करने पर परिवार को पीटा

लखनऊ संवाददाता। मूलरूप से हरदोई के माधवगंज की रहने वालीं अंजली कनौजिया अपने माता–पिता के साथ विकल्पखंड में रहती हैं। अंजली के अनुसार, शनिवार शाम पिता ने झोपड़ी के सामने जेपटो कर्मी सूरज को नशा करते देखा। मना करने पर सूरज 20 साथियों के साथ लौटा। आरोपियों ने लाठी–डंडों से माता–पिता को पीटा और बीच बचाव करने पर उन्हें भी मारा। हंगामा बढ़ने पर आरोपी भाग निकले। पुलिस को सूचना दी गई, घायलों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि सूरज हिरासत में है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित, अपराधियों की कोई जाति नहीं : रमेश मिश्रा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में रविवार को बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के लिए कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है और योगी सरकार इस मोर्चे पर प्रभावी ढंग से काम कर रही है। विधायक मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकारें कानून व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफल नहीं रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी वर्ष होने के कारण विपक्ष सरकार की छवि खराब करने का षड्यंत्र कर रहा है। उनके अनुसार, हाल के समय में सामने आए अधिकांश मामलों में शामिल करीब 70 प्रतिशत अपराधियों का संबंध समाजवादी पार्टी से रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एनकाउंटर, संपत्तियों की कुर्की और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई के कारण अपराधियों में कानून का भय बना है। विधायक ने कहा कि कुछ युवा प्रलोभन में आकर गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जिससे अपराध की घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि सरकार कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड के आरोपी रवि यादव के एनकाउंटर के बाद परिजनों द्वारा उठाए गए जातिगत सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक मिश्रा ने कहा कि सरकार की नजर में अपराधी की कोई जाति नहीं होती। चाहे वह ठाकुर, ब्राह्मण, यादव या किसी अन्य बिरादरी से हो, अपराध करने पर उसके खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जाती है। सरकार की नीति स्पष्ट है कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई जाति देखकर नहीं, बल्कि अपराध के आधार पर की जाती है।

जमीन के विवाद में दो भाइयों में खूनी संघर्ष, छह घायल

लखनऊ संवाददाता। महिगवां के गुलालपुर अकड़ा गांव में रविवार सुबह जमीन के विवाद में दो भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें दोनों पक्षों से छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। गांव निवासी कमलेश के अनुसार, वह और चंद्रपाल सगे भाई हैं। रविवार सुबह करीब आठ बजे घर के सामने सहन की जमीन को लेकर चंद्रपाल के बेटों सोनू, मोनू और संतोष से विवाद हुआ। आरोप है कि सोनू और मोनू ने फावड़े व कुल्हाड़ी से हमला किया। उनके परिवार के मखाना, प्रमोद, क्रांति और नीरज घायल हुए। दूसरे पक्ष से चंद्रपाल और एक अन्य व्यक्ति भी चोटिल हुए। पुलिस ने मामला शांत कराकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इंस्पेक्टर राधेश्याम मौर्या ने बताया कि पांच लोगों को अधिक चोटें लगी हैं। दोनों पक्षों से कोई तहरीर नहीं मिली है।

शाम को झमाझम बारिश के बाद राजधानी में मौसम हुआ सुहाना

लखनऊ संवाददाता। राजधानी में रविवार को मौसम ने फिर करवट ली। सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच धूप–छांव का खेल देखने को मिला। दोपहर बाद घने बादलों ने आसमान को पूरी तरह ढक लिया। दिन में ही अंधेरा छाने के साथ करीब 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने लगी। शाम करीब 5 बजे तेज बारिश भी शुरू हो गई। शाम तक 2.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। आधे से पौन घंटे तक चली बारिश के बाद शाम को राजधानी में मौसम सुहाना हो गया। लोग देर शाम को पार्कों और पुराने लखनऊ के इलाके में सैर को निकले। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से भरी हवाओं के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। सोमवार को भी बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री की बढ़त के साथ 36.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री की बढ़त के साथ 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

आरक्षण को सभी क्षेत्रों में लागू करने की मांग, भीम आर्मी ने सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में भीम आर्मी जय भीम संगठन ने सोमवार को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण व्यवस्था को लोकतंत्र के सभी स्तंभों में लागू करने की मांग की। ज्ञापन का नेतृत्व संगठन के जिलाध्यक्ष कंचन राव ने किया। ज्ञापन में माग किया गया है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। संगठन ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। जिलाध्यक्ष कंचन राव ने कहा कि षजिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारीष के सिद्धांत के आधार पर सरकारी और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने तथा विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े बैकलॉग पदों को भरने की भी मांग उठाई। संगठन ने शिक्षा के क्षेत्र में नीट जेईई और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संविधान के प्रावधानों एवं यूजीसी के नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ज्ञापन में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने, कथित फर्जी एनकाउंटर और गोकशी के झूठे मामलों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई। इसके अलावा लैटरल एंट्री व्यवस्था समाप्त करने और जातिगत जनगणना कराकर आबादी के आधार पर हिस्सेदारी तय करने की मांग उठाई गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की।

सत्यापन में यूपीटीईटी के 200 प्रमाण पत्र संदिग्ध, नियमानुसार होगी कार्रवाई

लखनऊ संवाददाता। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में 200 प्रमाणपत्र फर्जी व संदिग्ध पाए गए हैं। यह प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) द्वारा वर्ष 2011 से 2021 के बीच जारी किए गए थे। इनकी जांच जून 2025 से मई 2026 के बीच की गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शिकायतों के आधार पर गाजियाबाद, गोंडा, देवरिया, अमेठी, शामली, संभल, बलरामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, सीतापुर, मथुरा, गाजीपुर, भदोही, बलिया और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों से भेजे गए मामलों की जांच की गई। जांच में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आई हैं। हाल ही में सीतापुर जनपद से सात शिक्षकों के टीईटी प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए पीएनपी भेजे गए थे। जांच में सभी प्रमाणपत्र असत्य पाए गए।

कुछ क्षेत्र में दूना हो जाएगा कृषि भूमि का सर्किल रेट

लखनऊ संवाददाता। मोहनलालगंज तहसील के गौरा, बेंदौवा और भसंडा में जनपदीय मार्ग से सटी कृषि भूमि का प्रस्तावित सर्किल रेट अभी 51 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर था। जबकि प्रस्तावित रेट 98 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है। गौरा और भसंडा में सामान्य कृषि भूमि का सर्किल रेट 37 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, जबकि जिलाधिकारी ने इसे 70 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर करने का प्रस्ताव दिया है। सरोजनीनगर के ग्राम खटोला में जनपदीय मार्ग, संपर्क मार्ग, आबादी से सटी और सामान्य भूमि का सर्किल रेट क्रमशः 50, 45, 50 व 35 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है।

कलेक्ट्रेट सभागार में मेधावी छात्र हुए सम्मानित

अयोध्या।सोमवार को हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2026 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रथम 10 हाईस्कूल एवं प्रथम 10 इण्टरमीडिएट मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह जिला कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित किया गया।इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रोली सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता गोसाईगंज विधायक अभय सिंह के अलावा सीडीओ के के सिंह ने ने संयुक्त रूप से मॉ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।कार्यक्रम मे प्रदेश स्तर पर आयोजित मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह की प्रशंसा व सराहना करते हुए जनपद के प्रदेश स्तर पर स्थान प्राप्त छात्रा अराध्या जयसवाल कक्षा–10 राज्य स्तरीय रैक 09वीं संस्था कनौसा कान्वेट गर्ल्स इ0का0 अयोध्या, एवं प्राची पाण्डेय कक्षा 10 राज्य स्तरीय रैक 10वीं संस्था कनौसा कान्वेट गर्ल्स इ0का0 अयोध्या तथा अम्बिका कसौधन कक्षा 10 रैंक 10वीं एम0एस0नाज इण्टर कालेज सुचित्तागंज अयोध्या का मंच से सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश स्तर स्थान प्राप्त तीनो विद्यार्थियों को एक लाख रूपया का चेक, टेबलेट, मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।जनपद स्तर पर आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार के रूप में इक्कीस हजार का साकेंतिक चेक, मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और जिला विद्यालय निरीक्षक की तत्परता से धनराशि खाते में हस्तातरण किया गया।इस मौके पर डीआईओएस डॉ0 पवन कुमार तिवारी की प्रशंसा करते हुए नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को भविष्य में आगे बढ़ने की शुभकामना देते हुए छात्र/छात्राओं को मेडल पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।माननीय विधायक गोसाईगंज अभय सिंह ने भी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सम्बोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजना की प्रशंसा करते हुए छात्र/छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य एवं राष्ट्र के लिए समर्पित होकर भविष्य में अपनी योग्यता की पहचान बनाते हुए जनपद का नाम देश में रोशन करें इन्ही आशीष वचनों के साथ विद्यार्थियों अभिभावकों/शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यो के प्रयास की सराहना करते हुए जनपद अयोध्या का नाम देश व प्रदेश स्तर पर रोशन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मेडल पहना कर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले विद्यालयों को प्रधानाचार्य, प्रबधाक, व शिक्षकों की सराहना की। इस मौके पर ओंकार नाथ प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज, कृष्ण कुमार प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज ददेरा,सिस्टर लिंडा प्रधानाचार्या कनौसा कान्वेट गर्ल्स इ0का0, प्रधानाचार्या राजकीय बालिका इ0का0 अयोध्या, प्रदीप कुमार सहित कई लोग शामिल रहे।

शहर के चौराहों पर ट्रैफिक लाइट व सीसीटीवी कैमरे बने शोपीस

(डाक्टर अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या।रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद शहर के अधिकतर चौराहों पर यातायात नियंत्रण करने के लिए तथा शहर वासियो को जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक लाइटों को लगवाया गया था जो कि इस समय शो पीस बने हुए हैं।बताते चले कि शहर के रिकाबगंज चौराहा सहित एक –दो चौराहों को छोड़ दे बाकी शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे ट्रैफिक लाइटो के साथ साथ सीसीटीवी शो पीस हुए हैं।जिसके चलते शहर के नाका, शांति चौक, फतेहगंज, रायबरेली चौराहा,देवकाली तिराहा, पुष्पराज चौराहा,देवकाली बाईपास, सिविल लाइन चौराहा, पुलिस लाइन चौराहा, टेढ़ी बाजार चौराहा सहित विभिन्न चौराहों पर घंटो जाम लगा रहता है।बताते चले कि शहर में यातायात को नियंत्रित करने के लिए बेनीगंज स्थित जलकल विभाग मे आईटीएमएस नियंत्रण कक्ष 27 दिसंबर 2022 को खोला गया था।जो अभी भी क्रियाशील है।इसी कक्ष से वहां पर बैठे कर्मियों द्वारा शहर के विभिन्न चौराहे की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।बताते चले कि यातायात को नियंत्रित करने व शहर को जाम से मुक्ति रखने के लिए यातायात विभाग ने चिन्हित 20 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।जिसकी निगरानी एक नियंत्रण

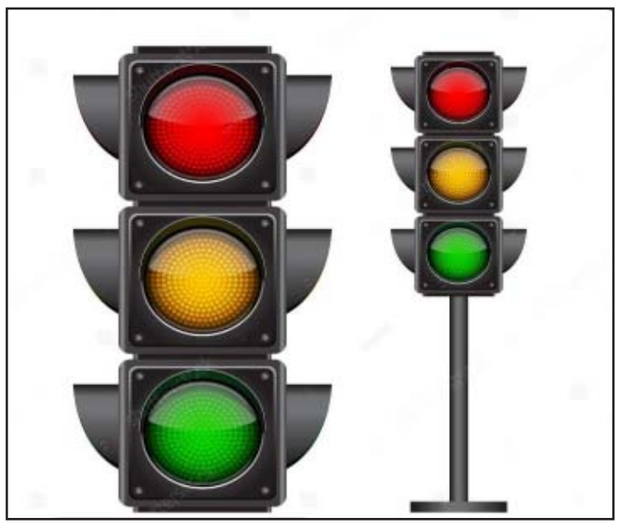

कक्ष में बैठे कर्मियों द्वारा किया जाता है।कार्यालय कर्मियों के मुताबिक शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे लगभग 20 ट्रैफिक लाइट काम कर रहे हैं और जो बंद है वह या तो सीवर पाइपलाइन के चलते बंद है।फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा के समय यह सिस्टम बहुत ही क्रियाशील था। उसे समय भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के पास लगे लाउडस्पीकर के माध्यम से नगर निगम व यातायात कर्मी वाहन चालकों को अपने–अपने दिशाओं में चलने तथा उन पर नियंत्रित करने का कार्य करते थे साथ ही साथ आईटीएमएस कार्यालय में बैठे कर्मचारी यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों का चालान भी काटते थे लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है।वही आईटीएमएस नियंत्रण कक्ष कर्मी ने बताया कि शहर में चौराहों पर लगी सभी ट्रैफिक लाइटें काम कर रही है।कहा कि यातायात विभाग के निर्देश पर शहर में स्थित विभिन्न चौराहों पर लगे ट्रैफिक लाइटों को चालू तथा बंद किया जाता है।इसके साथ ही अयोध्या में आयोजित विभिन्न पर्वो,मेले व अद्धालुओ के भारी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व सभी चौराहों पर पैनी नजर रखी जाती है।साथ ही यातायात विभाग के निर्देशों पर नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर कार्यवाही भी की जाती है।

आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के अथर्व वेद त्रिपाठी सहित 5 मेधावी छात्रों ने किया जेईई एडवांसड 2026 शानदार प्रदर्शन

अयोध्या।आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के 5 छात्रों ने जेईई एडवांसड 2026 शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एसआरजी डाक्टर अंबिकेश त्रिपाठी तथा प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षिका अर्चना त्रिपाठी के मेधावी पुत्र अथर्व वेद त्रिपाठी ने 181 अंकों के साथ एआईआर 2351 हासिल कर इस संस्था के साथ–साथ अपने माता–पिता तथा जिले का नाम रोशन किया है। इस

बात की जानकारी पत्रकार वार्ता में देते हुए विजय पाठक, शिवम त्रिपाठी, आयुष गुप्ता, दुर्गेश राय, दीपक सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि उनके अलावा प्रियांशु श्रीवास्तव को एआईआर 5006 मिली।जबकि राघव निगम, विश्वास राय और प्रज्ज्वल तिवारी ने भी सफलता पाई।नतीजे आज घोषित हुए।एईएसएल के रीजनल डायरेक्टर डी.के. मिश्रा ने सभी छात्रों को बधाई दी और इसे कड़ी मेहनत और अनुशासित तैयारी का नतीजा बताया।प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अकादमिक हेड इंजीनियरिंग शिवम त्रिपाठी, डॉ दीपक सिंह, ब्रांच हेड बिजय पाठक ने सभी मेधावी व चयनित छात्रों को बधाई दी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एएलएस एंबुलेंस सेवा गंभीर मरीजों के लिए हो रही वरदान साबित

अयोध्या।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एलएलएस एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी एम ई डी केयर 365 के द्वारा संचालित की जा रही है।बीती रात बस एक्सीडेंट हादसे में विक्रमजोत ओवर ब्रिज पर खड़ी खराब डीसीएम से टकराने के बाद रोडवेज की बस ब्रिज से नीचे गिर गई जिसमें घायल मरीज विवेक राय ग्राम सलहोपुर पोस्ट सलहोहपुर जिला देवरिया को सर में गंभीर चोट लगने के कारण मेडिकल कॉलेज अयोध्या भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद मरीज की हालत को देखते हुए मरीज को हायर सेंटर केजीएमयू लखनऊ के लिए रेफर किया जाता है। मेडिकल स्टाफ के द्वारा ए एल एस एम्बुलेंस पर फोन किया जाता है। मरीज के लिए ए एल एस एंबुलेंस संख्या यूपी32इजी6239 प्रदान की जाती

है। ए एल एस एंबुलेंस के ईएमटी समरजीत के द्वारा मरीज को एंबुलेंस में शिफ्ट किया जाता है और मरीज को ईएमटी के द्वारा ऑक्सीजन और लगातार ड्रिप देते हुए और मॉनिटरिंग करते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ मैं मरीज को सुरक्षित इमरजेंसी में भर्ती करवा दिया जाता है।यूपी32इजी6239 के पायलट केसरी नंदन शुक्ला का भी योगदान रहा गाड़ी को मानक स्पीड और सेफ ड्राइव की जिससे मरीज के घर वाले एंबुलेंस सेवा से बहुत प्रभावित है कह रहे थे।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एंबुलेंस सेवा बहुत अच्छी है।

महिला पुलिस ने भेजा जेल

अयोध्या।महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने शांति भंग मे दो आरोपियों को जेल भेजा। इस संबंध मे उन्होंने बताया कि जेल भेजे गए आरोपियों

की पहचान मुकेश कुमार गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय कृपा शंकर गोस्वामी निवासी ग्राम पधारवा पोस्ट बरेटा थाना तारुन व बैजनाथ गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय राम समूझ निवासी ग्राम कोनी गोसाई का पुरवा थाना कुमारगंज के रुप मे हुई।

फोरलेन हादसा : ट्रक चालक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज

गोरखपुर, संवाददाता। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अजवनिया गांव के पास फोरलेन पर हुए भीषण सड़क हादसे में बाल–बाल बचे ट्रक चालक की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्रक चालक ने डंपर चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने और सीधी टक्कर मारने का आरोप लगाया है, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई थी। इसमें डंपर चालक व खलासी की मौत हो गई थी। राजस्थान के अलवर निवासी ट्रक चालक लियाकत अली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 27 मई को बिहार के सेमरहावा से मक्का लोड कर हरियाणा जा रहा था। 28 मई की सुबह 5:45 बजे अजवनिया गांव के सामने फोरलेन पर दोनों दिशाओं के वाहन एक ही लेन से चल रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर में आग लग गई, जो देखते ही देखते ट्रक तक फैल गई। चालक लियाकत अली और क्लीनर अरमान किसी तरह कूदकर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि दोनों को चोटें आईं। क्लीनर का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया। तहरीर के अनुसार, आग लगने से ट्रक में लदी मक्का की खेप के साथ करीब 1.30 लाख रुपये नकद, दो मोबाइल फोन और अन्य जरूरी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। दूसरी ओर डंपर चालक और खलासी आग की चपेट में आकर बाहर नहीं निकल सके और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद फोरलेन पर लंबा जाम लग गया था और दमकल की पांच गाड़ियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। प्रारंभिक जांच में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने एक ही लेन से दोनों तरफ के वाहनों के संचालन की बात स्वीकार की है। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों और जिम्मेदारी तय करने में जुटी है।

यूरिया की कालाबाजारी व थोक दर घोषित करने की मांग को लेकर भाकियू ने किया जोरदार प्रदर्शन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। यूरिया खाद की कालाबाजारी, टैगिंग, थोक दर घोषित करने, यूरिया खाद की कमी को दूर करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन जनपद अयोध्या द्वारा जिला कृषि अधिकारी अयोध्या के कार्यालय पर किसान महापंचायत किया गया महापंचायत में नव आगंतुक जिला कृषि अधिकारी सौरभ वर्मा दलबल के साथ पहुंचकर समस्याओं को जायज ठहराते हुए समाधान के लिए समय मांगा भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने इस शर्त पर कि थोक विक्रेताओं की बैठक करके थोक दर घोषित करने हेतु बैठक की तिथि घोषित कर दिया जाए परंतु जिला कृषि अधिकारी द्वारा थोक विक्रेताओं के साथ मीटिंग करने की तिथि ना बताने के कारण आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों व किसानों ने प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए, यूरिया की कालाबाजारी रोकने की मांग करते हुए कमिश्नरी का घेराव किया और 16 सूत्रीय ज्ञापन अपर आयुक्त प्रशासन को सौंप कर समस्या समाधान करने की मांग किया गया।किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं को फुटकर दर से भी अधिक दाम पर यूरिया बेचने के कारण किसानों को महंगे दामों पर यूरिया मिल रही है और जबरदस्ती गुणवत्ता विहीन वस्तुओं की टैगिंग

की जा रही है जो किसी भी दशा में उचित नहीं है घनश्याम वर्मा ने जिला कृषि अधिकारी व जिला प्रशासन से मांग किया कि थोक दर घोषित कर दिया जाए जिससे किसानों को भी फूट कर दर 266. 50 पैसे प्रतिबोरी यूरिया मिल सके।और पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा यूरिया खरीदने की ऑनलाइन व्यवस्था किसी भी दशा में उचित नहीं है जिसको लागू नहीं होना चाहिए।जिला अध्यक्ष राम गणेश मौर्य ने स्मार्ट मीटर को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग करते हुए प्रतिदिन 20 घंटा लगातार विद्युत आपूर्ति की मांग किया।मध्यांचल सचिव सूर्यनाथ वर्मा ने अपने संबोधन में कहां की जिन–जिन गांवों में विद्युत लाइन नहीं गई है सिंचाई हेतु विद्युत नहीं मिल पा रही है और डीजल इंजन से सिंचाई करना पड़ रहा है उन किसानों के लिए डीजल फ्री होना चाहिए।महंगाई का विरोध करते हुए प्रदेश महासचिव अभयराज ब्रह्मचारी व श्री राम वर्मा ने कहा कि डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े।हुए दाम वापस लिए जाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 10 परसेंट विद्युत बिल में वृद्धि की गई है तत्काल वापस लिया जाए।किसान महापंचायत में भारी संख्या में नर नारी व किसान तथा भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थिति दर्ज कराकर जिला प्रशासन पर किसान समस्याओं के समाधान का दबाव बनाया।किसान महापंचायत को जिला उपाध्यक्ष शंकरपाल पांडे,भागीरथी वर्मा, फरीद अहमद, भोला सिंह टाइगर, मोहम्मद अली, सिद्धू भारती,सती प्रसाद वर्मा, सरबजीत वर्मा,राजदेव यादव,राम अवध किसान, रविंद्र मौर्य,तहसील अध्यक्ष रवि शंकर पांडे, महेंद्र वर्मा, संतोष वर्मा, राजेश मिश्रा, जगदीश यादव,रामू चंद्र विश्वकर्मा, जितेंद्र कुमार,मंसाराम वर्मा,वेद प्रकाश पांडे, राम सुमेर भारती, प्रेम शंकर वर्मा, बाबूराम तिवारी ,सुनील पाल ,राहुल वर्मा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकास वर्मा, विवेक पटेल, विजय प्रकाश ,अश्वनी शर्मा, जवाहरलाल तिवारी,लक्ष्मीकांत तिवारी, परशुराम प्रधान, काली प्रसाद मौर्य, मुन्ना कनौजिया, उर्मिला निषाद, आसमानिशा, जमुना देवी गीता देवी लालमति सुनीता देवी आदि लोगों ने संबोधित किया।

रेलवे में नौकरी के नाम पर 70 युवकों से ठगी, बर्खास्त कर्मचारी पर एफआईआर

गोरखपुर, संवाददाता। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 70 युवकों से ठगी के मामले में शाहपुर पुलिस ने रेलवे के बर्खास्त कर्मचारी पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि रेलवे से बर्खास्त कर्मचारी दीपक कुमार सिंह ने एक प्राइवेट विज्ञापन जारी कराया और फिर ऑनलाइन रुपये लेकर युवकों को 23 मई को इंटरव्यू के लिए बुलाया। युवकों के यांत्रिक कारखाना आने के बाद उन्हें ठगी की जानकारी हुई, जिसके बाद रेलवे के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी ने शाहपुर थाने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक, 23 मई को विभिन्न जिलों से करीब 70 युवक रेलवे के यांत्रिक कारखाना परिसर में इंटरव्यू देने पहुंच गए। युवकों के हाथ में नियुक्ति और इंटरव्यू से जुड़े दस्तावेज थे, लेकिन कारखाना प्रशासन को इस भर्ती प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं थी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने पर अधिकारियों को शक हुआ और जांच शुरू की गई। पूछताछ में सामने आया कि सभी युवकों को एक ही माध्यम से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। जांच में पता चला कि आरोपी दीपक कुमार सिंह ने खुद को रेलवे से जुड़ा अधिकारी बताकर सोशल मीडिया और इंटरनेट माध्यमों से भर्ती का प्रचार कराया था। युवकों को रेलवे में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया और उनसे पंजीकरण, टूल्स तथा अन्य औपचारिकताओं के नाम पर पांच हजार से दस हजार रुपये तक लिए गए। भुगतान के लिए मोबाइल फोन पर क्यूआर कोड भेजा जाता था, जिसके माध्यम से रकम जमा कराई जाती थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दो दिनों के भीतर 60 से 70 युवक इंटरव्यू के लिए यांत्रिक कारखाना पहुंच चुके थे। लगातार अभ्यर्थियों के आने और मामले की जानकारी फैलने के बाद कारखाना प्रशासन सतर्क हो गया। इसके बाद वरिष्ठ कार्मिक अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जांच कराई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह फर्जी थी और इसके पीछे पूर्व रेलकर्मी दीपक कुमार सिंह की भूमिका सामने आई। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश : नौकरी–पढ़ाई के नाम पर ठगी, 10 सदस्य गिरफ्तार, 453 बंधक मुक्त

गोरखपुर, संवाददाता। नेपाली नागरिकों को नौकरी, पढ़ाई और नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अधिक कमाई का सपना दिखाकर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का कसया पुलिस की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया है। संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आठ पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज, नकदी, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। एसपी केशव कुमार के निर्देशन में एएसपी सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा सीओ कसया कुन्दन कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कसया, सर्विलांस सेल, स्वाट टीम और एसटीएफ गोरखपुर की संयुक्त टीम ने बीते शनिवार को कसया थाना क्षेत्र अंतर्गत कसया नगर में दर्जनों जगह पर छापेमारी कर आरोपितों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार गिरोह नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को नौकरी और पढ़ाई का लालच देकर कुशीनगर बुलाता था। यहां उनसे प्रशिक्षण, पंजीकरण और अन्य शुल्कों के नाम पर रकम वसूली जाती थी। जांच के दौरान 453 नेपाली नागरिकों को गिरोह के प्रभाव से मुक्त कराकर सुरक्षित नेपाल भेजा गया। पुलिस ने आरोपितों के पास से नौ फर्जी आधार कार्ड, 60 बॉन्ड पेपर, एक लैपटॉप, कई अंगूठियां, 60,320 रुपये भारतीय मुद्रा और 14,290 रुपये नेपाली मुद्रा बरामद की है। पुलिस ने नेपाल राष्ट्र निवासी दीपक थापा, ओम प्रकाश चौलागाई, नीमा शेरपा, गनेश खत्री, सोजन्य संतन, ज्ञानेन्द्र यादव, विशाल तामंग समेत भारतीय कसया परसौना निवासी सर्वेश प्रताप राव को गिरफ्तार किया है।

जल्द होगा यूपी के दूसरे फ्लैटेड फैक्टरी काम्प्लेक्स का लोकार्पण, मिलेगा रोजगार

गोरखपुर, संवाददाता। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में उद्यमिता और औद्योगिक विकास को नई उड़ान मिलने जा रही है। हाल के वर्षों में बड़े औद्योगिक यूनिट्स स्थापना की श्रृंखला के बीच गीडा में एमएसएमई यूनिट्स की भी नई कतार नजर आने जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप इसका जरिया बना है गीडा के सेक्टर–13 में बना फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स। यह प्रदेश का दूसरा निर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है जिसका लोकार्पण 3 जून (बुधवार) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस अवसर पर सीएम योगी, गीडा औद्योगिक क्षेत्र में एलआईजी–ईडब्ल्यूएस आवासीय परिसर का उद्घाटन करने के साथ करीब 208 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने गोरखपुर के गीडा में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है। प्लग एंड प्ले मॉडल वाले इस कॉम्प्लेक्स के जरिये लघु एवं मध्यम उद्यम के विस्तार से उद्यमिता विकास और तेज होगा। गीडा के औद्योगिक सेक्टर–13 में 42.50 करोड़ रुपये की लागत से बना फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, प्रदेश में अपनी तरह का दूसरा कॉम्प्लेक्स है। एमएसएमई विभाग की तरफ से पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कानपुर में शुरू किया गया है। गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक बताती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, गीडा के औद्योगिक सेक्टर–13 में 10860 वर्गमीटर (2.68 एकड़) क्षेत्रफल में 42. 50 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार है। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के इंडस्ट्रियल ब्लॉक (जी3) में 80 इकाइयों के लिए प्रति इकाई का क्षेत्रफल 97.51 वर्गमीटर एवं एमिनिटी/यूटीलिटी ब्लॉक (जी1) में 42 इकाईयों हेतु, प्रति यूनिट इकाई का क्षेत्रफल 20.89 वर्गमीटर है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।